दस लाख करोड़ की होगी पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी

मंत्री नन्दी ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ की बैठक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (यूपीजीआइएस) में आए 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के प्रयास सरकार के स्तर से शुरू कर दिए गए हैं। इस कड़ी में मंगलवार को औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने पिकअप भवन सभागार में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीसीडा, गीडा, सीडा, यूपीडा और इन्वेस्ट यूपी के कार्यों, तैयारियों एवं योजनाओं की समीक्षा की। ताकि अगस्त माह में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में करीब दस लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की आधारशिला रखी जा सके। बैठक में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी भी उपस्थित रहे।

मंत्री नन्दी ने सभी अधिकारियों को यूपीजीआइएस-2023 की तर्ज पर प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के भव्य आयोजन और अधिक से अधिक निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। कहा, ऐसे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाए जिसमें कम भूमि पर अधिक निवेश प्रस्तावित हो। स्पष्ट कहा कि जिन उद्यमियों ने बड़े पैमाने पर जमीनें ली हैं और उनका अधिकतर हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसी जमीनों को वापस लिया जाए। नन्दी ने कहा कि निवेश को लेकर प्रदेश में जो सकारात्मक माहौल बना हुआ है, उसे बनाए रखना है। उद्यमियों का जो भी बकाया है, उसका जल्द से जल्द भुगतान करें। उद्यमियों को सब्सिडी देने में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बने इसके लिए सभी प्राधिकरणों और विभागों को रोड मैप बना कर कार्य करना होगा। इस मौके पर आइआइडीसी मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव उद्योग नरेंद्र भूषण, प्रमुख सचिव अनिल सागर, सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, एसीईओ इन्वेस्ट यूपी प्रथमेश कुमार, सीईओ नोएडा ऋतु महेश्वरी, सीईओ यमुना अथारिटी अरुणवीर सिंह, सीईओ यूपीसीडा मयूर महेश्वरी, एमडी पिकअप पियूष वर्मा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी (फाइल फोटो)

- कहा, लैंड बैंक बढ़ाएं सभी विकास प्राधिकरण, अनुपयोगी जमीन ली जाए वापस

19 हजार में से 13 हजार एमओयू को धरातल पर उतारने का लक्ष्य

सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए दस लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर लाते हुए शिलान्यास का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए सभी विभागों की जवाबदेही तय की गई है। यूपीजीआइएस में प्राप्त 19 हजार एमओयू में से 13 हजार एमओयू को धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। 25 सेक्टोरल पालिसी में से 13 का शासनादेश जारी हो चुका है। 31 मार्च तक सभी नीतियों का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।

लैंड बैंक बढ़ाने के प्रयास में जुटा यूपीसीडा

यूपीसीडा के सीईओ मयूर महेश्वरी ने बताया कि यूपीजीआइएस में यूपीसीडा को 3 .13 लाख करोड़ के 527 एमओयू प्राप्त हुए हैं। जिसके सापेक्ष 1 .60 लाख करोड़ के एमओयू को पहले चरण में धरातल पर उतारने का लक्ष्य तय किया गया है। यूपीसीडा के पास 15,000 एकड़ जमीन है। लैंड बैंक और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

सेरेमनी के लिए विभागवार तय लक्ष्य

विभाग	लक्ष्य(करोड़ रु. में)
यूपीसीडा	1,60,000
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	1,00,000
आइटी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग	1,00,000
शहरी विकास विभाग	1,00,000
आवास विभाग	80,000
नोएडा विकास प्राधिकरण	60,000
एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन	50,000
उच्च शिक्षा विभाग	50,000
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्रा.	40,000
यमुना अथारिटी	35,000
बागवानी विभाग	35,000
पर्यटन विभाग	30,000
ऊर्जा विभाग	30,000
हैंडलूम और टेक्सटाइल विभाग	25,000
उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्रा.	15,000
डेयरी विकास विभाग	10,000
आबकारी विभाग	10,000
खाद्य और नागरिक आपूर्ति	10,000
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	10,000
मेडिकल हेल्थ विभाग	10,000
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट	8000
चिकित्सा शिक्षा विभाग	7,000
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन	7,000
सहकारिता विभाग	5000
वन विभाग	5000
व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग	4000
तकनीकी शिक्षा विभाग	3000
पशुपालन विभाग	1000

नोविप्रा की 60 हजार करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास की तैयारी

नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने यूपीजीआाइएस में 88,822 करोड़ रुपये के कुल 371 एमओयू किए गए थे। इसके सापेक्ष ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 60 हजार करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारते हुए शिलान्यास कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि यूपीजीआइएस में यमुना अथारिटी ने 79,780 करोड़ रुपये के 120 एमओयू साइन किए थे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 30,605 करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतारने का लक्ष्य है।